

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 44/2018/75 एलआर एक्ट

1. राधेश्याम पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीकिशन पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मिनाक्षी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरिता पुत्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्त

—: बनाम :-

1. लखीराम पुत्र भैराराम जाति योगी निवासी पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोंडेंट/प्रार्थी

2. श्रीकवंर पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अशोक पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनील पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सतीश पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सुनीता पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंटस/अप्रार्थीगण

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.01.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 20/2017 अनवानी लखीराम बनाम श्रीकवंर आदि

श्री शहजाद हुसैन अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 2 ता 6

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 7

निर्णय

दिनांक -19.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की भूमि मे से

रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्यों का खण्डन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंड का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संबंधित रास्ता की स्वीकृति के संबंध में मुख्यतः यह विधिक आपत्ति की गई थी कि जिस भूमि पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है प्रश्नगत प.न. 29/215 के कि.न. 25 में कोई रास्ता स्वीकृत ही नहीं है। प्रश्नगत प.न. 29/315 कि.न. 25 के साथ चिपता हुये बैजानिव दक्षिणी दिशा के चक 15 पीबीएन के प.न. 29/316 के कि.न. 4 व 5 में गै0मु0 जंगलात भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कि.न. 25 को कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तो उसमें से 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है, जो रास्ता प.न. 30/316 के कि.न. 1 ता 5 में स्वीकृत है जिसका प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में हवाला दिया है वह रास्ता प.न. 30/316 के कि.न. 1 में आकर बन्द हो जाता है क्योंकि उसके आगे चक 15 पीबीएन के प.न. 29/316 के कि.न. 4, 5 में गै0मु0 जंगलात भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में कोई भी रास्ता स्वीकृत राजस्व रिकार्ड नहीं है। इसलिये प्रथमतः चक 15 पीबीएन के प.न. 29/316 के कि.न. 5 में रास्ता स्वीकृत होना आवश्यक है जिसे कि चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 के कि.न. 25 में प्रवेश किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता के संबंध में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त होने का हवाला दिनांक 17.10.17 की फर्दअहकाम में किया है उसके लिए आदेश न्यायालय द्वारा दिया ही नहीं गया न ही ऐसा फर्दअहकाम में दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट के समय अपीलांटस व उनके अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी गई जिस कारण से अपीलांटस अपने पक्ष को तहसीलदार के सामने नहीं रखे सके और ना ही रिपोर्ट पर आपत्तियां पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251क तथा इसके तहत बने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधान के विपरीत पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। प्रत्यर्थी द्वारा चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 कि.न. 25 में रास्ता स्वीकृत करवाया गया जबकि इसके विपरीत किला नं. 16 में रास्ता स्वीकृत नहीं है इससे स्पष्ट है कि मौका पर कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर अपीलांटस की भूमि में मध्य में रास्ता स्वीकृत कर

अपीलांट की भूमि को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया है जिसकी वजह से काश्त करने, सिंचाई करने व आवागमन में अपीलांटस को अत्याधिक कठिनाई होगी। रेस्पो0 सं. 1 की भूमि को प.न. 29/315 के कि.न. 8, 13, 18, 23 में मौका पर रास्ता चालू है इसके संबंध में एक रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जिसमें स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी की भूमि को प.न. 29/315 कि.न. 8, 13, 18, 23 में रास्ता चालू है जिसका प्रयोग प्रार्थी लखीराम अपनी आराजी में आता जाता है जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 342, आरआरटी 2017 पेज 1088, डीएनजे 2018 पेज 65, डीएनजे 2018 पेज 36 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 के कि.न. 25/0.013 है0 रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्वी दिशा रास्ता स्वीकृत किया है उपरोक्त स्वीकृत रास्ता के बदले चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 के कि.न. 15/0.013 है0 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 को करवाकर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने का आदेश दिया गया है जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है, पूर्व में कभी रास्ता नहीं चलने का मिथ्या तर्क है। रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है प्रश्नगत रास्ता के अलावा रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 अपनी भूमि में ना तो सिंचाई कर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। अपीलांट को रास्ता भूमि के ऐवज में चिपती हुई भूमि भी देने के आदेश पारित किये गये हैं जिससे अपीलांट को भूमि के संबंध में क्षति कारित नहीं हुई है। अपीलांट ने बिना किसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. 2 ता 6 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2018 को पारित किया जो आधार हीन है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/ रेस्पो0 सं. 2 ता 6 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य में रास्ता स्वीकृत कर प्रार्थीगण की भूमि को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया है जिसकी वजह से काश्त करने, सिंचाई करने व आवागमन में

अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 को अत्याधिक कठिनाई पैदा होगी। रेस्पो0 सं. 1 की भूमि को प.न. 29/315 के कि.न. 8, 13, 18, 23 में मौका पर रास्ता चालू है इसके संबंध में एक रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जिसमें स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी की भूमि को प.न. 29/315 कि.न. 8, 13, 18, 23 में रास्ता चालू है जिसका प्रयोग प्रार्थी लखीराम अपनी आराजी में आता जाता है जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन न करके विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 7 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 कि.न. 25 में 0.013 है0 रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्वी दिशा रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा रास्ता भूमि के बदले में प्रार्थी की भूमि प.न. 29/315 कि.न. 15 में 0.013 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का यह तर्क है कि किला नं. 25 में रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि कि.न. 16 में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया है, के खण्डन में रेस्पो0 के तर्क एवं रिकार्ड के अनुसार कि.न. 16/1/0.013 है0 भूमि रेस्पो0 लखीराम की है जिसका उपयोग उपभोग रेस्पो0 सं. 1 रास्ते हेतु कर सकता है तथा यहां यह भी निर्देशित किया जाना उचित है कि रेस्पो0 सं. 1 कि.न. 16/1/0.013 है0 दक्षिण से उत्तर पूर्वी ओर रास्ते हेतु उपयोग करेगा और उक्त कि.न. 16/0.013 रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख दर्ज रहेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा रास्ते भूमि के बदले में चिपती हुई भूमि अप्रार्थी/अपीलांट को दिये जाने का अंकन किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पुष्टि योग्य है।
8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2018

को यथावत रखा जाता है तथा रेस्पो0 सं. 1 को निर्देशित किया जाता है कि चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 मु.न. 50 के कि.न. 16/0.013 है0 दक्षिण से उत्तर पूर्वी ओर रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग करेगा और उक्त कि.न. 16/0.013 रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख दर्ज रहेगी तथा उक्त कि.न. 16/0.013 है0 दक्षिण से उत्तर पूर्वी ओर रास्ता के रूप में दर्ज करने हेतु तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार पीलीबंगा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

